International Journal of Engineering Research & Management Technology
ISSN: 2348-4039
Sep-Oct-2017 Volume 4, Issue-5
Email: editor@ijermt.org www.ijermt.org

ग्रामीण विकास, शासन और सेवा वितरण पर योजना के प्रभाव का आकलन करे

Dr. Suraj Kumar Gobhil

Asstt.Professor (Economics)

Govt.E.V.P.G. College Korba

Distt - Korba(C.G)

सार

यह अध्ययन दूरदराज के क्षेत्रों में शासन और सेवा वितरण पर ग्रामीण विकास योजना के प्रभाव का आकलन करता है। बुनियादी ढांचे में सुधार, आजीविका को बढ़ाने और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई इस योजना ने ग्रामीण समुदायों को काफी प्रभावित किया है। शोध तीन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: ग्रामीण विकास, शासन और सेवा वितरण। ग्रामीण विकास इस योजना के कारण सड़क, सफाई और स्वच्छ पानी तक पहुंच सहित बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे जीवन की स्थिति बेहतर हुई है। आधुनिक कृषि तकनीकों और वित्तीय सहायता की शुरुआत के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता बढ़ी है। शासन इस योजना ने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर स्थानीय शासन को मजबूत किया है। इसने स्थानीय निकायों और समुदायों को सशक्त बनाया है, जिससे बेहतर निर्णय लेने और संसाधन आवंटन सुनिश्चित हुआ है। शासन प्रक्रियाओं में नागरिक भागीदारी में वृद्धि देखी गई है, जिससे जमीनी स्तर पर अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक शासन हुआ है सेवा वितरण में प्रौद्योगिकी का उपयोग दक्षता में सुधार और भ्रष्टाचार को कम करने में भी एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। निष्कर्ष रूप में, इस योजना का ग्रामीण विकास, शासन और सेवा वितरण पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। हालाँकि, इन लाभों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिसके लिए निरंतर निगरानी, सामुदायिक जुड़ाव और अनुकूली रणनीतियों की आवश्यकता होती है।

मुख्य शब्द : *ग्रामीण विकास, सेवा वितरण, प्रभाव*

परिचय

ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है, अक्सर अविकसितता, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, खराब शासन और आवश्यक सेवाओं तक सीमित पहुँच से संबंधित चुनौतियों का सामना करते हैं। इन चुनौतियों के जवाब में, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, शासन को मजबूत करने और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी पहल और योजनाएँ लागू की गई हैं। ऐसी योजनाओं की सफलता न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बल्कि समग्र राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन एक विशिष्ट ग्रामीण विकास योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर केंद्रित है जिसे लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को बदलने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना को बुनियादी ढाँचे के विकास, कृषि उत्पादकता, सामाजिक कल्याण और शासन सहित ग्रामीण जीवन के कई पहलुओं को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इन क्षेत्रों में सुधार करके, योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक समावेशी और सतत विकास मॉडल बनाने का प्रयास करती है। ग्रामीण विकास इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह सीधे ग्रामीण आबादी की आजीविका को प्रभावित करता

है। बुनियादी ढाँचे का विकास, जैसे कि सड़कें, स्वच्छता सुविधाएँ और स्वच्छ पानी तक पहुँच, इन क्षेत्रों में रहने की स्थिति और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाने वाली पहल आवश्यक हैं। इस योजना का एक और मुख्य फोकस शासन है, जिसमें स्थानीय शासन संरचनाओं को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए गए हैं। विकास पहलों के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रभावी शासन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन किया जाए, निर्णय समावेशी रूप से लिए जाएं और ग्रामीण आबादी की जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए।

सेवा वितरण का तात्पर्य ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं के प्रावधान से है। इन सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित होती है, जिससे स्वास्थ्य परिणामों, शैक्षिक प्राप्ति और समग्र कल्याण में असमानताएँ पैदा होती हैं। इस योजना का उद्देश्य नई सुविधाएँ स्थापित करके, मौजूदा सुविधाओं को उन्नत करके और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर सेवा वितरण में सुधार करना है। यह परिचय इस बात की विस्तृत जाँच के लिए मंच तैयार करता है कि योजना ने इन तीन क्षेत्रों - ग्रामीण विकास, शासन और सेवा वितरण - को कैसे प्रभावित किया है और ग्रामीण समुदायों के लिए इसके व्यापक निहितार्थों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। अध्ययन का उद्देश्य ऐसी योजनाओं की प्रभावशीलता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करना और उनकी सफलता या विफलता में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करना है, अंततः भविष्य की ग्रामीण विकास नीतियों के लिए सिफारिशें प्रदान करना है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. परिवहन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और ऊर्जा पहुंच सहित बुनियादी ढांचे में सुधार की जांच करें।
2. ग्रामीण परिवारों के बीच कृषि उत्पादकता और आय के स्तर में बदलाव का आकलन करें।
3. गैर-कृषि रोजगार अवसरों सहित स्थायी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में योजना की भूमिका का विश्लेषण करें।

ई-गवर्नेंस: नागरिक कल्याण, सेवा वितरण और ग्रामीण विकास में महत्व

1990 के दशक की शुरुआत में आईसीटी की स्वीकृति के साथ शासन की अवधारणा में बड़ा परिवर्तन हुआ। इस अवधि के दौरान, प्रौद्योगिकियों को मुख्य रूप से सार्वजनिक सेवाओं और सूचनाओं के वितरण के लिए तैनात किया गया था और इसे लोकप्रिय रूप से 'ई-गवर्नेंस' के रूप में जाना जाता था। धीरे-धीरे लोकतांत्रिक देशों के लिए शासन के मुख्य रणनीतिक मुद्दों में अपने नागरिकों की 'आवाज़ों' को शामिल करना प्रासंगिक हो गया। परिणामस्वरूप, 'ई-गवर्नेंस' के प्रारंभिक संस्करण को 'ई-गवर्नेंस' के अपने अधिक व्यापक अवतार के माध्यम से पहचाना जाने लगा। हम पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं (BPAC 110 की इकाई 13 देखें)। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) ग्रामीण भारत के विकास और आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण विकास में ई-गवर्नेंस स्थानीय नागरिकों के जीवन में काफी बदलाव ला सकता है। यह स्थानीय लोगों और नागरिकों के बीच की खाई को पाट सकता है, यह शिक्षा, विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित जानकारी जैसी सेवाएँ प्रदान कर सकता है, जो अंततः लोगों को उनके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से सुधारने में मदद करती हैं। ग्रामीण आबादी के पास ऐसे मुद्दे हैं जो देश के विकास को गति देते हैं।

सरकार ने आईसीटी पद्धतियों को अपनाया है और डिजिटल इंडिया अभियान जैसे अभियान शुरू किए हैं, और इसके कार्यान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इन पहलों और परियोजनाओं को व्यवहार में लाने का उद्देश्य हर क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाकर एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना है। अब तक, ई-गवर्नेंस ने लोगों के जीवन को इतना आसान बना दिया है कि लोग बिना समय बर्बाद किए और कम लागत में सिर्फ़ एक टच से अपना काम कर सकते हैं। स्थानीय लोगों के पास न केवल अपने रिकॉर्ड/भूमि रिकॉर्ड तक पहुँच है, बल्कि वे अब उनके कामकाज की निगरानी भी कर सकते हैं। स्थानीय लोगों के साथ सिस्टम का यह जुड़ाव राष्ट्र के विकास को बढ़ावा दे रहा है। इन पहलों और प्रथाओं ने नागरिकों को आत्म-विकास करने, उनके आत्म-सम्मान को बढ़ाने और उन्हें रोजगार देने में मदद की है।

डिजिटल विभाजन

विकासशील देशों में हाशिए पर पड़ी ग्रामीण आबादी साल दर साल डिजिटल विभाजन को बढ़ाती जा रही है। संसाधनों, शिक्षा और ज्ञान तक सीमित पहुँच के साथ, ग्रामीण आबादी को सतत विकास के लिए सरकारी स्तर पर उचित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। डिजिटल विभाजन ग्रामीण आबादी के साथ-साथ देश के विकास के लिए भी खतरा है। यह आधुनिक तकनीक और सूचना का उपयोग करने के लिए आबादी में पहुँच और क्षमताओं के असमान वितरण को संदर्भित करता है। हालाँकि, डिजिटल अंतर के कारण होने वाले ये अंतर राष्ट्रों, राज्यों, जिलों, पुरुषों और महिलाओं, ग्रामीण और शहरी, अमीर और गरीब या यहाँ तक कि साक्षर और निरक्षर के बीच भी मौजूद हो सकते हैं। यह समझना मौलिक है कि आबादी में लोगों की क्रय शक्ति अलग-अलग होती है, आबादी के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग स्मार्ट फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट सेवा आदि जैसे नए आईसीटी उपकरणों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। आबादी में कुछ व्यक्ति पर्याप्त रूप से साक्षर (बुनियादी शिक्षा और डिजिटल कौशल) भी नहीं हो सकते हैं या आईसीटी उपकरणों का उपयोग करने के लिए भाषाई बाधाओं से बंधे हो सकते हैं। सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझने पर, यह कहा जा सकता है कि यह विभाजन आबादी के कुछ वर्गों जैसे महिलाओं पर सामाजिक बाधाओं से भी उत्पन्न होता है जिन्हें आईसीटी उपकरणों तक पहुँच की अनुमति नहीं है। इसलिए, डिजिटल अंतर को पाटने वाले स्वदेशी रूप से विकसित ई-गवर्नेंस तंत्र को कानूनी ढांचे के साथ विकासशील देशों में लागू किया जाना चाहिए। जबकि ई-गवर्नेंस और आईसीटी उपकरण डिजिटल विभाजन से चुनौती भरे हैं, वे प्रभावी और कुशल तरीके से उपयोग किए जाने पर अंतर को पाटने की क्षमता रखते हैं। उन्हें प्रौद्योगिकी, प्रशासन, वित्तीय, प्रबंधकीय और विनियामक प्रक्रियाओं को नया रूप देने के लिए शामिल किया जाना चाहिए। इससे ग्रामीण समुदायों के उत्थान और सशक्तिकरण के साथ-साथ सरकारों द्वारा सेवा वितरण में आसानी के लिए आशाजनक लाभ हैं। कृषि पद्धतियों में सुधार से लेकर, भूमि रिकॉर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करने, सरकार को उनकी प्रथाओं के लिए सही राशि वसूलने में सक्षम बनाने, मौसम की भविष्यवाणी करने में सक्षम बनाने, बेहतर शिक्षा देने से लेकर बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूक करने तक, ई-गवर्नेंस प्रथाओं ने नागरिकों को विभिन्न प्रथाओं के बारे में खुद को जागरूक करने और अपने जीवन में लागू करने के लिए सही मात्रा में डेटा का उपभोग करने का हर संभव अवसर दिया है। इस कार्यान्वयन ने एक बड़ा बदलाव लाया है जो सरकार को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है। हालाँकि, दौड़ अभी खत्म नहीं हुई है। एक विकसित राष्ट्र के लिए रास्ता अभी लंबा है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर अभी भी कम है, लोग शिक्षा और इसके महत्व को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। ग्रामीण संदर्भ में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में साक्षरता दर और भी कम है। भले ही सरकार ने काफी बदलाव किए हों, लेकिन ग्रामीण नागरिक बेहतर जीवन स्थितियों और जीवन की गुणवत्ता की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। इसलिए, देश के लिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक विकसित देश बनने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है।

आकांक्षी जिले

सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने के लिए, भारत में 111 अल्पविकसित जिलों को बदलने के लिए 2018 में आकांक्षी जिले नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" के आदर्श वाक्य का पालन करते हुए जिलों में लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह तीन मुख्य सिद्धांतों - अभिसरण (केंद्र और राज्य योजनाओं का), सहयोग (नागरिकों और केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों के बीच जिला टीमों सहित), और जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा के साथ जिलों को मजबूती और सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करने पर केंद्रित है। राज्य द्वारा संचालित, यह कम लटके फलों की पहचान करके और जिले की रैंकिंग की प्रगति की मासिक जाँच करके तत्काल सुधार को प्राथमिकता देता है। 5 व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों - स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास और बुनियादी ढाँचे के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में की गई वृद्धिशील प्रगति के आधार पर, रैंकिंग निर्धारित की जाती है। सहकारी संघवाद की भावना में, यह सेवा प्रावधानों को आसान बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग और प्रोत्साहन करता है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के दंडेवाड़ा जिले में शिक्षा तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए आईसीटी मॉडल हैं। प्रोग्रामर अन्य जिलों की सफलताओं और गलतियों से सीखने का अवसर देता है, खासकर नए जिलों से - पिछड़े हुए जिले शुरुआती प्रदर्शन करने वालों द्वारा की गई गलतियों से बच सकते हैं। इस प्रकार, विकेंद्रीकरण और कार्यान्वयन के माध्यम से, तीनों सिद्धांत राष्ट्र की प्रगति को बढ़ावा देते हैं।

भारत सरकार: ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस की पहल

भारत गांवों का देश है और ग्रामीण क्षेत्रों की समग्र समृद्धि, वृद्धि और विकास को बेहतर बनाने और बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने कई परियोजनाएं शुरू की हैं। दरअसल, ग्रामीण भारत में शुरू की गई कुछ योजनाओं ने सरकारी सेवाओं में काफी सुधार किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS), ऑनलाइन आयकर, ऑनलाइन केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विशिष्ट पहचान पत्र और ई-ऑफिस जैसी कुछ योजनाओं ने संबंधित क्षेत्रों के विकास को गति दी है और देश के आर्थिक विकास में योगदान दिया है। महाराष्ट्र में SETU परियोजना और कर्नाटक में भूमि परियोजना जैसी कुछ राज्य स्तरीय परियोजनाएँ उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान कर रही हैं और लोगों के साथ-साथ सरकार का समय और पैसा बचा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण भारत का सामाजिक-आर्थिक विकास हो रहा है। ग्रामीण विकास के लिए कुछ परियोजनाओं का उल्लेख नीचे किया गया है:

ई-चौपाल

ई-चौपाल शब्द की उत्पत्ति 'चौपाल' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गाँव में खुले मैदान में बैठक। भारत एक ऐसा देश है जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्र कृषि प्रधान है। भले ही यहाँ बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण हुआ हो, लेकिन कृषि व्यवसाय के मामले में बड़े पहलू को कवर करने के लिए जानी जाती है। हर व्यवस्था में बीच में मध्यस्थ होते हैं, और वह भी इस व्यवस्था में। किसान फसलों के उत्पादक होते हैं और नागरिक/स्थानीय लोग/संगठन/व्यक्तियों के समूह उपभोक्ता होते हैं, लेकिन बीच में एक मध्यवर्ती स्तर होता है जिसे थोक विक्रेता/खुदरा विक्रेता के रूप में जाना जाता है। मध्यवर्ती स्तर पर व्यक्ति अपना मार्जिन निर्धारित करता है, जिसका असर किसानों और उनकी उत्पादन लागत पर पड़ता है, जिसके कारण बाज़ार में बाधा उत्पन्न होती है। इसे दूर करने के लिए, ITC के कृषि व्यवसाय प्रभाग द्वारा ई-चौपाल की शुरुआत की गई थी। इस पहल ने किसानों को बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के सीधे उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद बेचने में मदद की। इससे अंततः किसानों को बिना किसी बाधा के अपना सही मुनाफ़ा

कमाने में मदद मिली। ई-चौपाल की सेटिंग में, प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए पीसी (पर्सनल कंप्यूटर) इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई (यूपीएस) दी जाती है।

ज्ञानदूत

जनवरी 2000 में बेरोजगार शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षित करने, सूचना केन्द्र चलाने के लिए सूचना केन्द्रों का संचालन करने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। सूचना केन्द्रों का स्वामित्व ग्रामीण इंट्रानेट प्रणाली के पास है, जो किफायती है और बेरोजगार लोगों के लिए फायदेमंद है। वे कृषि, शिक्षा, महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं। इस नेटवर्क के अंतर्गत लगभग 600 लोग आते हैं और अपनी आजीविका के लिए कमाई कर सकते हैं।

आकाशगंगा

यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों के दूध उत्पादकों को उनके खातों और उत्पादकता का प्रबंधन करने के लिए एक आईसीटी प्रदान करके उनकी मदद करने के लिए शुरू की गई थी। इसका पहला मॉडल गुजरात में उत्तरसंडा डेयरी सहकारी समिति में लागू किया गया था। इस सोसायटी में, प्रत्येक किसान को एक पहचान पत्र आवंटित किया गया है, जिसकी पहचान रॉ मिल्क रिसीविंग डॉक (आरएमसीडी) पर की जाती है। जब कोई किसान अपने दूध के ड्रम को वहाँ खाली करता है, तो डॉक वसा की मात्रा जैसे सभी आवश्यक तत्वों को मापता है और पर्सनल कंप्यूटर में रिकॉर्ड करता है।

किसान कॉल सेंटर

किसान कॉल सेंटर अप्रैल 2002 में शुरू किए गए थे और मुख्य रूप से किसानों द्वारा उठाए गए भाषा संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इसे कृषि और सहकारिता विभाग और कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इस परियोजना ने किसानों को दूरसंचार सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के साथ सहज होने में मदद की क्योंकि अधिकांश किसान सरकार द्वारा शुरू की गई नवीनतम तकनीकों और उन तक पहुँचने के तरीकों से अवगत नहीं थे। इस परियोजना ने किसानों को अधिकारियों से जोड़कर कृषि क्षेत्र में अंतर को पाट दिया। उन्हें विभिन्न तकनीकों और संचालनों के बारे में पता चला जिनका उपयोग वे अपनी फसल-उपज प्रथाओं में कर सकते हैं।

टाटा किसान केंद्र

टाटा किसान केंद्र की शुरुआत टाटा केमिकल लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में की थी। इसकी अनूठी विशेषता जीआईएस यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली उपग्रह की मदद से काम करती है और खेती से जुड़े तत्वों, मिट्टी, पानी, जमीन आदि के बारे में जानकारी देती है। यह सड़कों और पुलों के बुनियादी ढांचे और सेटिंग के क्षेत्र को भी कवर करती है; और पूरे राज्य में कीटों के हमलों का पता लगा सकती है। इस तकनीक ने किसानों को कम हानिकारक और कम उपज वाली फसलों के साथ अपनी उत्पादकता बढ़ाने में मदद की। ये पहल ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के क्षेत्र में उछाल के रूप में साबित हुई और इनके कार्यान्वयन से ई-गवर्नेंस का उद्देश्य पूरा होता है।

भारत में ई-गवर्नेंस:

ई-गवर्नेंस में तुलनात्मक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में योगदान देने की सबसे अधिक क्षमता है। भारत में, ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस का उपयोग अपेक्षाकृत धीमा है, क्योंकि ई-गवर्नेंस के लिए अधिकांश धन और प्रयास देश के शहरी क्षेत्रों में ही मौजूद हैं। 1990 के दशक से भारत सरकार ने समाज को आर्थिक लाभ प्रदान करने के लिए इंटरनेट सुविधाओं के माध्यम से ई-गवर्नेंस, दूरसंचार और टेलीमेडिसिन, ई-कॉमर्स और सामुदायिक सूचना केंद्रों जैसी कई संचार तकनीकों और पहलों को लागू करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण विकास में ई-गवर्नेंस के लिए आईसीटी के अनुप्रयोगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: 1) ग्रामीण लोग विभिन्न ई-गवर्नेंस या आईसीटी उपकरणों के माध्यम से प्रशासन की निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं जो सफल विकास परियोजनाओं के निर्माण, उनके कार्यान्वयन और निगरानी में मदद करेंगे। 2) प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाएँ जो नागरिकों के लिए फायदेमंद है; 3) सभी प्रकार की सूचनाओं और तकनीकी ज्ञान तक पहुँच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण, और 4) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के लिए बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना। 5) भ्रष्टाचार को कम करना और अनुभव को कम करके समय और पैसा बचाना। 6) असेवित समूहों को सूचना प्रदान करना। 7) भारत में अधिकांश राज्य सरकारों ने मोबाइल, कंप्यूटर आदि में आईसीटी और इंटरनेट सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से ई-गवर्नेंस की पहल की है। 8) बागगेटल के अनुसार, "ई-गवर्नेंस एक सरकार-से-लोगों और लोगों से सरकार का दृष्टिकोण है, जिसके माध्यम से लोग सीधे सरकारी रिकॉर्ड, नियमों और उन अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो उनके दैनिक जीवन को चलाने के लिए आवश्यक हैं... 9) यह लोगों और प्रशासन के बीच बिचौलियों को खत्म करके प्रशासन में एक मजबूत प्रतिरोध भी चलाता है जो आम लोगों के लिए फायदेमंद है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए भारत में ई-गवर्नेंस पहल:

भारत को अपनी आजादी के 70 साल से अधिक हो गए हैं लेकिन अभी भी कुल आबादी का 69.84% (जनगणना रिपोर्ट, 2011) ग्रामीण इलाकों में रहता है। बुनियादी ढांचे और सेवाओं जैसे सड़क, पोषण, स्कूली शिक्षा और सरकारी सेवाओं आदि के मामले में ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों की तुलना में पीछे हैं। ग्रामीण भारत की इन प्रचलित विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, ई-गवर्नेंस ने सूचना प्रवाह के प्रवेश द्वार के रूप में और ग्रामीण भारत के विकास कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अपनी विश्वसनीयता प्राप्त की है। निस्संदेह भारत सरकार ने डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए 2015 में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया अभियान जैसे काफी प्रयास किए हैं और ई-गवर्नेंस और आईसीटी इसके सफल कार्यान्वयन के लिए एक उपकरण साबित हुए हैं। चैंबर्स के अनुसार ग्रामीण विकास एक रणनीति है जो लोगों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करके खुद को और अपने परिवार को लाभान्वित करने में सक्षम बनाती है हालांकि, ग्रामीण विकास क्षेत्र में ई-गवर्नेंस का उपयोग भारत में अपेक्षाकृत धीमा रहा है, क्योंकि ग्रामीण बुनियादी ढांचे की स्थिति खराब है और ग्रामीण लोगों में जागरूकता की कमी है। धीमी गति से तैनाती के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्र के विकास में ई-गवर्नेंस की कई पहल हैं। उदाहरण के लिए, भारत में ग्रामीण विकास के लिए CRISP, NEGP, NIC, ई-चौपाल, ज्ञानदूत, जागृति ई-सेवा, आकाशगंगा, TKK, किसान कॉल सेंटर जैसे ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन काम कर रहे हैं। ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस के विभिन्न उपकरणों या तकनीकों के कार्यान्वयन से ग्रामीण नागरिकों के बीच तेज़, पारदर्शी, जवाबदेह, कुशल और प्रभावी संचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलेगा बल्कि सरकार का समय और लेन-देन लागत भी बचेगी।

भारत में ई-गवर्नेंस की चुनौतियाँ:

नागरिकों और प्रशासन के बीच संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ई-गवर्नेंस की शुरुआत की गई थी। लेकिन भारत सरकार को इन तकनीकों और तरीकों को लागू करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार

के सामने आने वाली कुछ समस्याएँ या चुनौतियाँ नीचे सूचीबद्ध हैं। निरक्षरता - भारत सरकार ने ग्रामीण भारत में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ और परियोजनाएँ शुरू की हैं, लेकिन यह अभी भी शहरी साक्षरता दर से बहुत दूर है। ग्रामीण भारत में साक्षरता दर 67.67% है, जिसमें ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर 77.15% है। लेकिन महिला साक्षरता दर काफी कम है जो केवल 57.93% है। अधिकांश लोग आईसीटी उपकरणों के उपयोग को नहीं जानते हैं और इस प्रकार ग्रामीण लोग एगमार्कनेट, भूमि आदि जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जिसके लिए लाभार्थियों से पर्याप्त तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। विविध भाषाएँ - भारतीय समाज एक बहु-जातीय और विविध समाज है जहाँ प्रत्येक जातीय समूह के लोगों की अपनी संस्कृति और भाषाएँ हैं। यह देखा गया है कि भारत में अधिकांश ग्रामीण लोग केवल अपनी मूल भाषा ही बोलते हैं और वे मातृभाषा के अलावा अन्य भाषाओं से परिचित नहीं हैं। लेकिन सभी ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन अंग्रेजी को आधार भाषा के रूप में उपयोग करते हैं जिसे अधिकांश ग्रामीण लोग समझ नहीं पाते हैं। इस प्रकार, वे अक्सर सरकार और उसकी विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में उचित जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं।

जागरूकता का अभाव - अधिकांश ग्रामीण लोग सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण के लिए स्थापित किए गए आईसीटी उपकरणों और ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों के उपयोग के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं, ताकि लोगों और प्रशासन के बीच संचार नेटवर्क को बढ़ाया जा सके। हालाँकि, सरकार ने लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए रेडियो, टीवी पर अपनी परियोजनाओं को प्रसारित करने और बैनर लगाने आदि जैसी कई पहल की हैं, लेकिन इन सभी कार्यक्रमों से ग्रामीण लोग कम लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। बदलाव के प्रति हिचकिचाहट - ग्रामीण भारतीय लोग अपने दैनिक जीवन में किसी भी तरह के बदलाव को स्वीकार करने में रुचि नहीं रखते हैं, जो ग्रामीण जनता की अनिच्छुक प्रकृति को दर्शाता है। प्रशासन में ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन की शुरूआत ने आधिकारिक कार्यों की कार्यप्रणाली को मैनुअल से कंप्यूटरीकृत कर दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता द्वारा इसका स्वागत नहीं किया जाता है क्योंकि उनके मन में नई चीजें सीखने के लिए बहुत हिचकिचाहट होती है जिसके लिए उन्हें अधिक समय और प्रयास लगाने की आवश्यकता होती है।

बुनियादी ढांचा और परिचालन लागत - ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए दृढ़ आईटी बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जो भारत के अधिकांश गांवों में पिछड़ रहे हैं। भारत के अधिकांश दूरदराज के गांव अभी भी बिजली प्रणाली से नहीं जुड़े हैं। उन गांवों में टीवी देखना, इंटरनेट का उपयोग करना आम लोगों के लिए एक सपना बना हुआ है, जिसके कारण ग्रामीण लोग सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। ग्रामीण आईटी बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति में, लोगों को पास के शहर में जाना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों के माध्यम से जानकारी तक पहुँचने के लिए भारी मात्रा में पैसा देना पड़ता है। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि खराब आईटी बुनियादी ढांचा और भारी परिचालन लागत ई-गवर्नेंस पहल के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण टकराव बने रहे।

निष्कर्ष

ग्रामीण विकास योजना के मूल्यांकन से ग्रामीण विकास, शासन और सेवा वितरण के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। यह व्यापक मूल्यांकन ग्रामीण क्षेत्रों को बदलने में योजना की भूमिका को उजागर करता है और इसकी प्रभावशीलता और सुधार के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ग्रामीण विकास इस योजना ने बुनियादी ढांचे में काफी सुधार किया है, जिसमें परिवहन, स्वच्छता और जल आपूर्ति में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इन सुधारों से ग्रामीण समुदायों के लिए बेहतर जीवन स्तर और आर्थिक अवसर पैदा हुए हैं। इस योजना द्वारा सुगम कृषि उत्पादकता और

आय स्तरों में वृद्धि ने खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने में योगदान दिया है। हालाँकि, स्थिरता एक चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि इन लाभों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए निरंतर निवेश और समर्थन आवश्यक है। शासन स्थानीय शासन को मजबूत करना इस योजना की एक प्रमुख उपलब्धि रही है। बढ़ी हुई पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी के परिणामस्वरूप अधिक प्रभावी संसाधन प्रबंधन और निर्णय लेने की प्रक्रियाएँ हुई हैं। स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने से ग्रामीण आबादी में स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना बढ़ी है, जिससे अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक शासन में योगदान मिला है। फिर भी, किसी भी शेष शासन चुनौतियों का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए और प्रयासों की आवश्यकता है कि स्थानीय संस्थाएँ दीर्घावधि में प्रभावी रूप से काम करना जारी रख सकें। सेवा वितरण इस योजना के कारण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसी आवश्यक सेवाओं की पहुँच और गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। नई सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन से ये सेवाएँ दूरदराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में अधिक उपलब्ध हो गई हैं। प्रौद्योगिकी के एकीकरण ने सेवा वितरण को और बेहतर बनाया है, हालाँकि इन तकनीकी प्रगति का लाभ अधिकतम करने के लिए निरंतर रखरखाव और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। सभी के लिए समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए शहरी और ग्रामीण सेवा वितरण के बीच असमानताओं को दूर करना प्राथमिकता बनी हुई है। समग्र प्रभाव इस योजना का ग्रामीण विकास, शासन और सेवा वितरण पर सकारात्मक और परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है। इसने ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दिया है, अधिक प्रभावी शासन को बढ़ावा दिया है और आवश्यक सेवाओं तक पहुँच में सुधार किया है। हालाँकि, योजना की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए स्थिरता, शासन प्रभावशीलता और सेवा इक्विटी जैसी चुनौतियों का लगातार समाधान करने की आवश्यकता है।

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

[1] [1] अंत्योदय सरल, हरियाणा में योजना और सेवा वितरण में बदलाव। केस स्टडी। https://nceg.gov.in/sites/default/files/Antyodaya%20 Saral%20Haryana.pdf से लिया गया।

[2] भाटिया, ए. (2016)। भारत में ई-गवर्नेंस पहल के माध्यम से ग्रामीण विकास। आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। 01, 61-69।

[3] डिजिटल भूमि (भूमि प्रबंधन की व्यापक प्रणाली)। https://nceg.gov.in/sites/default/files/case_studies/Digital_Land.pdf से लिया गया।

[4] हीक्स, आर. (1999)। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, गरीबी और विकास। https://www. research gate से लिया गया। नेट/ प्रकाशन/ 334614932_सूचना और संचार प्रौद्योगिकी गरीबी और विकास

[5] हीक्स, आर. (2004)। विकासशील/संक्रमणकालीन देशों में ई-गवर्नेंस की सफलता और विफलता दर: एक अवलोकन। http://www.egov4dev.org/overview.htm से लिया गया

[6] भटनागर एस.सी., ई-गवर्नेंस; दृष्टि से कार्यान्वयन तक- केस स्टडीज़ के साथ एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका

[7] शेरोन एस. डावेस, ई-गवर्नेंस का विकास और निरंतर चुनौतियाँ

[8] एस.कुमार, “भारत में ई-गवर्नेंस”, इंपीरियल जर्नल ऑफ़ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, 2(2), 2016, 482-491.

[9] वी.बी. सिंह और एन. यादव, "ई-गवर्नेंस: भारत में अतीत, वर्तमान और भविष्य", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 53(7), 2012, 36-48।

[10] भारत सरकार, भारत के आंकड़े 2015, (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, 2015)

[11] ए.एच. रिज़वी, "भारत में ई-गवर्नेंस शैक्षिक परियोजनाओं का एक अध्ययन", ग्लोबल जर्नल फॉर रिसर्च एनालिसिस, 5(1), 2016, 37-38।

[12] एच. मिश्रा, "ई-गवर्नेंस सिस्टम में ग्रामीण नागरिक इंटरफेस का प्रबंधन: भारतीय संदर्भ में एक अध्ययन", प्रोक. 3 आरडी इंट. कॉन्फ. इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का सिद्धांत और अभ्यास, 2009।

[13] सीएसआर प्रभु, ई-गवर्नेंस: अवधारणाएँ और केस स्टडीज़, (नई दिल्ली: पीएचआई लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, 2004)। [14] भारत की जनगणना रिपोर्ट, 2011. भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय।